[Dr. K.V.P. Ramachandra Rao]

12.00 NOON

the Government shall take steps to ensure that these chemical pesticides and insecticides are not made available to people as over-the-counter drugs and are available as prescription drug and whoever buys this drug shall be explained how to use it in a safe way. These shall be made available to the people only on a prescription from qualified Agricultural Officers and it shall be used as medicine as and when required. The Government shall recognize the importance of education and training for safe use of pesticides.

I, therefore, urge upon the Government to immediately take steps to create awareness about the reasonable and rational use of pesticides and insecticides.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Promoting gherkins for export

* 196. SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether any steps have been taken to promote the growth and supply of gherkins after incessant rains and decline in exports, if so, the details thereof; and

(b) the steps taken to ensure strict compliance of certification requirements in case of gherkins meant for export, along with the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Gherkins is an export oriented vegetable crop cultivated in southern States of India. Cultivation of Gherkins, processing and export started in India during early 1990's with modest beginning in Karnataka and later extended to neighboring states of Tamil Nadu and Andhra Pradesh.

There has been no report from Gherkin growing states about the effects of incessant rains on Gherkin production and export.

This Ministry has provided assistance for Gherkin projects under the programs of NHB & also processing units under Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).

Gherkins are cultivated on contract farming model and entire gamut of cultivation practices and processing standards are adhered to by the Indian Gherkin manufacturers to produce Gherkin for the world market with quality control on the final produce as per the requirements of International market. There is provision of capacity building for fruits and vegetables cultivation including cultivation of Gherkins on package of practices, quality improvement and regulating use of pesticides for improving production and exports.

There is no mandatory requirement for quality certification for export of Gherkins. However, on the basis of country specific requirements, Export Inspection Council (EIC) India is the regulatory authority for issuance of quality certification. India exported 180820.87 MT of Cucumber and Gherkins, worth ₹ 942.72 crores during 2016-17, with major destinations being USA, Belgium, Russia, France and Spain.

As per the report of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), export of Gherkins during 2017-18 (April - September) has shown 27% growth over previous year (2016-17) during the same period.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, the agricultural exports are falling. Indian trade surplus in agricultural items fell from US $ 27174.2 in 2013-14 to about US $ 7833.8 in 2016-17. So, my question to the Minister is whether the Government has taken any step to bring out a policy framework for increasing exports of agricultural commodities, especially, when the GST is being applied. And, what is happening in refund of GST to the exporters?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय सभापति जी, मैं पहली बार प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था, वह एक commodity विशेष को लेकर था। ...**(व्यवधान)**...

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, my question is about agricultural exports.

MR. CHAIRMAN: Please.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: गर्किन नामक एक छोटा खीरा होता है, जिसके export को लेकर उनका प्रश्न था। इस सम्बन्ध में इन्होंने कहा था कि गर्किन का उत्पादन कम हुआ है और बरसात अधिक होने के कारण कम हुआ है। हमने इसका उत्तर दिया है कि उसका उत्पादन बरसात की अधिकता के कारण नहीं, अपितु बरसात कम होने के कारण हुआ है।

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, I seek your protection. He is not answering my question.

MR. CHAIRMAN: You have supplementary also. ...*(Interruptions)*... He is asking about exports.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः उस particular commodity के export के बारे में भी इन्होंने चिंता व्यक्त की थी, लेकिन 2016-17 के reference में 2017-18 में उसका export निश्चित रूप से बढ़ा है। 2016-17 में उसका जो export था, उसके comparison में production और export दोनों बढ़े हैं। सरकार उसके प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से National Horticulture Board के माध्यम से ऐसी फसलों का प्रोत्साहन करती है। इसके अतिरिक्त जो लचीली सहायता योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) है, उसके माध्यम से भी सरकार ऐसी फसलों के export को बढ़ाने के लिए और export oriented crops के लिए सहायता प्रदान करती है।

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, my question has not been answered. So, I seek your protection.

Sir, in the last few years we have seen that Indian agricultural exports are often banned in European Union and other countries. Indian mangoes were banned in EU and Indian rice was banned in Iran. Obviously, the schemes of the Government and the standards that they are implementing are not working. So my question is whether the Government is taking any step to make sure that when the crops are grown, these standards are met and they are not banned in foreign countries.

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल मुख्य रूप से निर्यात की दृष्टि से है। मेरी जानकारी में मेरे मंत्रालय के द्वारा इसमें जो प्रयत्न होते हैं, मैं उनका एक उदाहरण देना चाहूंगा। मुख्य रूप से निर्यात मंत्रालय इसकी monitoring करता है। जब हम सरकार में आए थे, तो European countries ने mango पर प्रतिबंध लगाया था। फिर हमने वहाँ की सरकार से बात करके उसके कारण पता लगाए और उसके तहत उनकी टीम के वैज्ञानिकों को हमने यह जानने के लिए बुलाया कि quality में क्या कमी है और हमारी जो testing labs हैं, उनमें क्या कमी है। वहाँ की टीम आई और 3 महीने तक अध्ययन करने के बाद उसने जो सुझाव दिया, हमने 3 महीने के अन्दर उसको पूरा किया। 6 महीने लगते-लगते आम का निर्यात फिर चालू हो गया। इसलिए quality की दृष्टि से जब कभी किसी देश के द्वारा प्रतिबंध लगता है, तो हम उससे तुरंत संपर्क करते हैं और अपने मानकों में सुधार करते हैं।

श्री पी.एल. पुनियाः सभापति महोदय, Gherkin खीरे की एक प्रजाति है, जिसकी खेती लघु और सीमांत कृषक करते हैं और यह अनुबद्ध कृषि के आधार पर होती है और इसका एक्सपोर्ट होता है। इसमें सिरका और एसिटिक अम्ल डाला जाता है, लेकिन सिरके और एसिटिक अम्ल पर GST 18 परसेंट लगाया गया है। इसकी सबसे ज्यादा खेती कर्णाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में होती है, जिसमें करीब एक लाख से अधिक लघु और सीमांत कृषक लगते हैं, लेकिन सारा मुनाफा बिचौलिये और एक्सपोर्टर्स ले जाते हैं।

महोदय, मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि कर्णाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के कितने लघु और सीमांत किसान Gherkin खीरे के उत्पादन को सीधे-सीधे एक्सपोर्ट भी करते हैं?

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति महोदय, इसकी खेती मुख्य रूप से तीन राज्यों में, संविदा कृषि मॉडल के आधार पर की जाती है। संविदा कृषि मॉडल के आधार पर उसके जो एक्सपोर्ट के मानक हैं, उसके तहत प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए हम मदद करते हैं। इसके लिए राज्य के पास भी एक RKY योजना है, जिसके माध्यम से वह भी मदद करता है, लेकिन इसका उत्पादन संविदा कृषि मॉडल पर मुख्य रूप से इन्हीं तीन राज्यों में होता है। हालांकि अन्य राज्यों में भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन जहां छोटे स्तर पर किसान इसका उत्पादन करते हैं, वह इन तीनों राज्यों में ही होता है, जिसका एक्सपोर्ट होता है।

श्री पी.एल. पुनियाः सर, मेरा सवाल, जो मार्जिनल फार्मर्स इसका एक्सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में था।

श्री सभापतिः वे मार्जिनल फार्मर्स के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री राधा मोहन सिंहः एक्सपोर्टर्स संविदा कृषि मॉडल के आधार पर ही खेती करवाते हैं, जिसका वे एक्सपोर्ट करते हैं।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the question has not been answered. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Question No.197. Shri Anand Bhaskar Rapolu.

Dealing with cyber crimes

*197.DR. T. SUBBARAMI REDDY: Will the Minister of ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether there are growing incidents of cyber crimes, including financial frauds, using bank cards and e-wallets;

(b) if so, the response of Government thereto;

(c) the measures taken to strengthen surveillance and legal framework to deal with cyber crimes; and

(d) whether police force has been adequately trained to deal with cyber crimes, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.